

Stuttering recovery: July factory output slows to 1.2%

Retails inflation rises 3.36% in August as food prices surge

OUR BUREAU

New Delhi, September 12

Nearly six months down, the fiscal year 2017-18, economic indicators continue to point to a muted recovery, watering down the government's expectations of returning to a high growth trajectory.

Official data released on Tuesday revealed a rising trend in retail inflation even as factory output remained subdued.

The index of industrial production (IIP) grew by a mere 1.2 per cent in July as against 4.5 per cent growth in July last year.

On a cumulative basis, factory output grew by just 1.7 per cent in the first four months of this fiscal.

IIP growth for June has also been revised downwards to a negative of 0.2 per cent from a dip of 0.1 per cent.

The low expansion in July this year seems to be due to negli-

gible growth of 0.1 per cent in the manufacturing sector that had seen low demand due to the roll out of the goods and services tax. However, electricity generation grew by a robust 6.8 per cent in July while mining expanded by 4.8 per cent.

Food price spike

Meanwhile, retail inflation in August climbed up to 3.36 per cent from 2.36 per cent in July as many food items such as vegetables saw a spike in prices.

The consumer food price index climbed up to 1.52 per cent in August from a decline of 0.36 per cent in July.

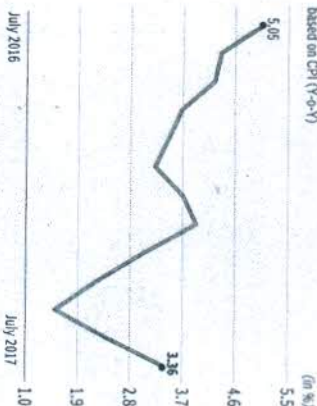
While prices are still under control and much below the central bank's target of four per cent, analysts believe that it may harden over the next few months.

"The CPI inflation is expected to harden further in September 2017, led by food and beverages, transport and communication, and housing, and cross four per cent by November 2017," said Aditi Nayyar, Principal Economist,

Worrying signs

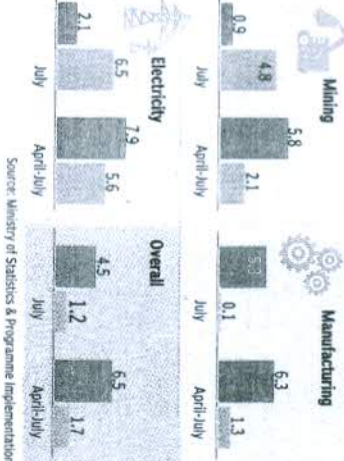
Retail Inflation

based on CPI (Y-o-Y)



IIP

■ 2016-17 ■ 2017-18 (Growth in %) (Base: 2011-12=100)



Source: Ministry of Statistics & Programme Implementation

ICRA, adding that factory output may also improve in August given the favourable base effect and the expected rebuilding of inventories prior to the festive season.

Expecting a turnaround in factory output in the coming months, Sunil Sinha, Principal Economist, India Ratings, said, "Both consumption and investment demand are weak. The

fiscal and monetary space is quite limited and the pick-up in growth is going to be a fairly slow and drawn out process notwithstanding the encouraging first month GST collections."

Industry is also hopeful of more rate cuts to boost demand and push up GDP growth. According to a recent study by industry chamber ASSOCHAM and consultancy EY, the manufactur-

ing sector needs to grow steadily at 14 per cent to 15 per cent annually over the next three decades for a sustained GDP growth of nine per cent to 10 per cent.

Compare this, with the first quarter GDP data that revealed that the economy grew at a three-year low of 5.7 per cent with manufacturing sector expansion pegged at 1.2 per cent. The second volume of the Eco-

nomics Survey has also warned of downward risks to its earlier forecast of 6.75 to 7.5 per cent GDP growth for 2017-18.

GST, note ban benefits

The Finance Ministry continues to be hopeful that the benefits of demonetisation and the roll out of the goods and services tax will increase the size of the formal economy and bring in more revenue.

But whether the gains accrue this fiscal or over the medium term is yet to be seen, though officials expect the economy to perform better in 2017-18 than last fiscal's 7.1 per cent GDP growth.

While tax receipts have shown an improvement this fiscal, private sector data such as the Nikkei Purchasing Managers' Index show that manufacturers and service providers have remained cautious post the implementation of GST.

A more thorough review will be undertaken towards the end of the year, when the Finance Ministry begins working on the Revised Estimates.

अगस्त में रिटेल महंगाई दर 5 महीने के टॉप पर पहुंची

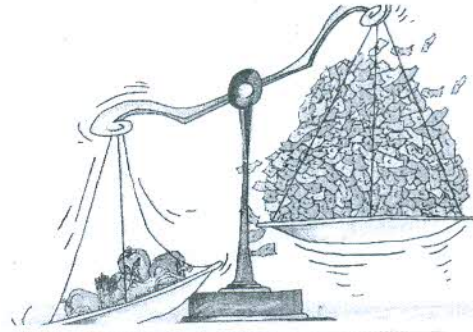
रिटेल इनफ्लेशन 3.36% हुई, जुलाई में आईआईपी 1.2% पर आई

विस | नई दिल्ली

सरकार को अब इकनॉमिक ग्रोथ में तेजी लाने के लिए रिटेल महंगाई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर जोरदार तरीके से काम करना होगा। इसका कारण है कि अगस्त में रिटेल महंगाई (सीपीआई) 5 महीने के टॉप पर पहुंच गई। अगस्त में रिटेल महंगाई दर 3.36 फीसदी रही, जबकि एक महीने पहले जुलाई में यह 2.36 फीसदी थी। यानी इसमें एक माह के भीतर 1 फीसदी की तेजी आई। वहीं पिछले साल अगस्त में यह दर 5.05 फीसदी थी। इससे पहले इससे ज्यादा महंगाई मार्च 2017 में 3.89 फीसदी थी।

दूसरी तरफ, जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) की ग्रोथ 1.2 फीसदी पर पहुंच गई। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार, जून में यह नेगेटिव जोन यानी -0.2 फीसदी थी। आईआईपी में तेजी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और माइनिंग आउटपुट में बढ़ोतरी की वजह से आई। इधर, इकरा की प्रिंसिपल इकनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि रिटेल महंगाई में तेजी बड़ी चिंता का विषय है। जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई में तेजी का अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था। मगर अगस्त में जिस तेजी के साथ रिटेल महंगाई दर बढ़ी है उससे लगता है कि रिटेल महंगाई दर अक्टूबर और नवंबर में ही 4 फीसदी को पार कर जाएगी। गौरतलब है कि आरबीआई ने मार्च-2018 तक रिटेल महंगाई दर को 4 फीसदी के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है।

इधर, इंडस्ट्री चैंबर एसोसिएम के डायरेक्टर जनरल डी एस रावित का कहना है कि यह खुशी की बात है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े नेगेटिव जोन से बाहर आ गए हैं, मगर अब भी उतनी तेजी नहीं आ पाई है, जितनी उम्मीद थी। सरकार को इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मार्केट में डिमांड में तेजी लानी होगी।



अगस्त में जिस तेजी के साथ रिटेल महंगाई दर बढ़ी है उससे लगता है कि रिटेल महंगाई दर अक्टूबर और नवंबर में ही 4 फीसदी को पार कर जाएगी

अदिति नायर, प्रिंसिपल इकनॉमिस्ट, इकरा

इसके लिए ब्याज दर कम करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई नीतिगत रिफॉर्म्स को अमल में लाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोरदार तरीके से सुधार करना होगा।

अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा सब्जियों और हाउसिंग इंडेक्स का हाथ रहा। हाउसिंग इंडेक्स में अगस्त में 9.4 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई, वहीं सब्जियों के इंडेक्स में 1.8 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

रिपोर्ट

एसोचैम और बाजार अध्ययन की रिपोर्ट

10 फीसदी विकास दर के लिए विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 15 फीसदी हो : सर्वे

नई दिल्ली, 12 सितम्बर (एजेसिया)। उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि नौ से 10 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर हासिल करने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र की तीन दशक तक वृद्धि दर 14 से 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

एसोचैम और बाजार अध्ययन करने वाली एजेसी ईवाई की संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट सस्टेनिंग इंडियाज ग्रोथ बाई एक्सीलरेटिंग मैनुयूफ. रिंग में कहा गया है कि तीव्र विकास दर हासिल करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में तेजी जरूरी है।

इसके बगैर तीव्र विकास दर हासिल करना संभव नहीं होगा। इसके मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने बहुत हद तक मौजूदा नियमन संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला है लेकिन फिर भी हर राज्य को अपने अपने विनिर्माण लक्ष्य की पूर्ति के लिए महत्ता के आधार पर नीतियों तथा नौकरशाही संबंधी बाधाओं का खुद हल निकालना होगा। हर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना करके या मौजूदा उद्योगों को जरूरी आधारभूत ढांचा मुहैया कराकर प्रत्यक्ष विकास करने की संभावना है। उद्योग संगठन के मुताबिक राज्यों के लिए विकास का सबसे बेहतर तरीका है वे उन उद्योगों पर



ध्यान केंद्रित करें, जहां वे कई कारणों से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे हैं। उन्हें कच्चे माल की उपलब्धता, मांग, उपभोक्ता उद्योग, लॉजिस्टिक, कुशक कामगारों की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए। जबरदस्त घरेलू मांग, बेहतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात में वृद्धि, आधारभूत ढांचे में अधिक खर्च, पूंजी प्रवाह और मददगार वित्तीय नीतियां ये बताती हैं कि देश का विनिर्माण क्षेत्र तेज विकास

की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह सकारात्मकता वित्तीय बाजार की स्थिरता के अलावा मुख्य रूप से जीएसटी के लागू होने से आयी है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र के विकास के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध दिखायी दे रही है। स्पोर्ट में कहा गया है कि देश का कुल निर्यात जुलाई 2017 में 3.94 प्रतिशत बढ़कर 2,254.38 करोड़ डॉलर पहुंच गया। यह लगातार ग्याहरवां महीना है, जब देश का निर्यात बढ़ोतरी पर रहा है। इसके अलावा चीन को किया जाने वाला इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात 123 फीसदी बढ़कर अप्रैल, जून तिमाही में 62.9 करोड़ डॉलर का हो गया।

रिपोर्ट: सब्जियों के दाम चढ़ने से मुद्रास्फीति पांच महीने के उच्चस्तर पर

महंगाई बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन घटा

एजेसी ►► नई दिल्ली

खुदरा मुद्रास्फीति की दर अगस्त महीने में बढ़कर पांच महीने के उच्चस्तर 3.36 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सब्जियों और फलों के दाम चढ़ने से खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। इससे पिछले महीने उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 2.36 प्रतिशत पर थी। अगस्त महीने का खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा मार्च, 2017 के बाद सबसे ऊंचा है। उस समय यह 3.89 प्रतिशत पर थी। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 1.52 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे पहले इसमें अपस्फीति थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार माह के दौरान रोजाना उपभोग वाले फल और सब्जियों की महंगाई दर बढ़कर क्रमशः 5.29 प्रतिशत और 6.16 प्रतिशत हो गई। यह जुलाई में क्रमशः 2.83 प्रतिशत और शून्य से 3.57 प्रतिशत नीचे थी। इसी तरह तैयार

यह 3.89 प्रतिशत पर थी। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 1.52 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे पहले इसमें अपस्फीति थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार माह के दौरान रोजाना उपभोग वाले फल और सब्जियों की महंगाई दर बढ़कर क्रमशः 5.29 प्रतिशत और 6.16 प्रतिशत हो गई। यह जुलाई में क्रमशः 2.83 प्रतिशत और शून्य से 3.57 प्रतिशत नीचे थी। इसी तरह तैयार



विनिर्माण पर ध्यान देने की जरूरत : एसोचैम

सरकार अगर जीडीपी वृद्धि दर 9 से 10 प्रतिशत बनाने रखना चाहती है तो उसे विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। एसोचैम-इंवाई के अध्ययन में यह कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से कई नियामकीय मुद्दों का समाधान हुआ है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिये राज्य सरकारों को नीकरशाही बाधाओं, बाध्यकारी नियमन और नीति जैसे मुद्दों का समाधान करना होगा।

भोजन, जलपान और मिठाई की श्रेणी में मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 1.96 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 0.43 प्रतिशत थी। इसी तरह परिवहन और संचार क्षेत्रों में भी महंगाई दर बढ़कर 3.71 प्रतिशत हो गई,

औद्योगिक उत्पादन घटकर 1.2 फीसदी

देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में कमी आयी है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि महज 1.2 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी माह में 4.5 प्रतिशत थी। इसका कारण विनिर्माण खासकर पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का खराब प्रदर्शन है। इससे रिजर्व बैंक पर नीतिगत दर में कटौती का दबाव बढ़ेगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने मंगलवार को यह आंकड़ा जारी किया।

जो जुलाई में 1.76 प्रतिशत थी। इसके अलावा मोटे अनाज और उत्पाद, मीट एवं मछली, तेल एवं बसा की महंगाई दर घटकर क्रमशः 3.87 प्रतिशत, 2.94 प्रतिशत और 1.03 प्रतिशत पर आ गई।

पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन घटा

अप्रैल-जुलाई के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत रही है जो पिछले साल इसी अवधि में 6.5 प्रतिशत रही थी। सूचकांक में 77.6 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई में घटकर 0.1 प्रतिशत रही जो 2016 के इसी महीने में 5.3 प्रतिशत थी। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन जुलाई में एक प्रतिशत घटा जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन आलोच्य महीने में 1.3 प्रतिशत घटा जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी।

बिजली व खनिज उत्पादन बढ़ा

हालांकि बिजली उत्पादन में जुलाई के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2016 के इसी महीने में 2.1 प्रतिशत थी। खनिज उत्पादन में भी आलोच्य महीने में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक साल पहले जुलाई महीने में 0.9 प्रतिशत थी। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र में वृद्धि दर जुलाई 2017 में 3.4 प्रतिशत रही। विनिर्माण क्षेत्र में कुल 23 औद्योगिक समूहों में से आठ में जुलाई 2017 में इससे पूर्व वर्ष के इसी महीने के मुकाबले वृद्धि हुई।

